signed on 17-1-1965. This says that the cost of exploration and exploitation will be shared under this agreement on this basis—fifty per cent of the produced oil would go to the NIOC and the remaining fifty per cent would be shared equally by the rest of the partners. So far as the other contracts are concerned we are going it. Iraq National Oil Company had given us exploration and exploitation for an area of 4,175 sq. miles and this was ratified on 20th November, 1973. They have also given us some seismic and drilling contracts. It is not for oil sharing, it is a sort of money to be paid according to different type of work to be done. Now that is not the total sum but different items having different accounts. Then the third one is Tanzania. It was in December 1975 that ONGC entered into an agreement and the contract is for drilling operations which started in June 1976 again to be paid for different type of work. That is not something on a wholesale basis that so much money and so much work.

DR SUBRAMANIAM SWAMY: I would like to know from the hon. Minister in view of the fact that ONGC is in some kind of cloud due to the activities of the previous Government, how do the terms and payments given by the foreign countries to us or the ONGC compare with what we give them for doing their operations within this country.

SHRI H. N. BAHUGUNA: These are contracts which are already signed and I have not applied my mind to the comparative figures or the competitive figures. But the hard point is that this has put us on the world map.

DR. VASANT KUMAR PANDIT: I would like to know from the hon. Minister the number of Indian technonogists and other type of personnel working in these countries on behalf of ONGC in Class, I, II, III and IV. Is there any condition laid down in the contract with regard to employing Indian personnel?

SHRI H. N. BAHUGUNA: So far as Tanzania and Iraq are concerned, we have hundred per cent complement of our officers and technical personnel of all clases. There are no Tanzanian or Iraqi nationals employed so far as these contracts are concerned. Our boys have gone there along with our equipment. So far as Iran is concerned, since there are more than one partner, therefore, there are different people. But we are also there.

SHRI K. LAKKAPPA: After entering into these agreements, have you thought of asking those governments for a reduction of oil price under these agreements?

SHRI H. N. BAHUGUNA: It is not something which is done because of the contract entered into with them, because it is a question of the quantity of oil in Iran which we get and not the price which we get. That oil sells at the same price as the world price or we bring it for ourselves. So far as Iraq is concerned, it is not a question of bringing oil. We are merely there on a job. The same is the case with Tanzania.

हिन्दी एवं अंग्रेजी माध्यमों के अध्यापक

*695. **श्री चतुर्भुज** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दी माध्यम के लिए चुने गये अध्यापकों तथा अंग्रेजी माध्यम के लिए चुने गये अध्यापकों के सम्बन्ध में अलग-अलग प्रवरता सूचियां बनाई जाती है ;

(ख) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं जबकि उनके चयन के लिए कसौटी अलग अलग है ; और

(ग) क्या दोनों वर्गों के अध्यापकों के चयन में एकरूपता लाई जायेगी ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI SHEO NARAIN): (a) Yes, Sir.

(b) and (c). Do not arise.

श्री चतुर्भुज : इस समय हिन्दी और अंग्रेजी के अध्यापकों की अलग अलग वरीयता सूचियां हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि उन में एकरूपता लाने के लिए क्या प्रयत्न किया जा रहा है।

SHRI SHEO NARAIN: The medium of instruction varies from zone to zone. Besides English and Hindi, in certain zonal regions, the students are taught in regional languages such as Bengali, Marathi, Telugu, etc.

श्री चतुर्भुज : अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया है। मैंने पूछा था कि रेलवे विभाग में हिन्दी और अंग्रेजी के अध्यापकों में एकरूपता लाने के लिए चयन-कार्य में क्या प्रक्रिया अपनाई जा रही है।

रेल मंत्री (प्रो० मधु दंडवते) : मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि सिर्फ हिन्दी ही नहीं, बल्कि सभी देशी भाषाओं के के लिए लिस्टें रखी हुई हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ अंग्रेजी अध्यापकों की लिस्ट रखी हुई है। ये अलग अलग लिस्ट्स इसलिए रखी हुई हैं कि अलग अलग जोन्स में मराठी, गुजराती, बंगाली और तमिल आदि भाषाओं में अध्यापन-कार्य किया जाता है। कई जगह अंग्रेजी में किया जाता है। हम लोगों की लगातार यह कोशिश रहती है कि अंग्रेजी भाषा के अध्यापक हों या देशी भाषाओं के, सभी अध्यापकों के लिए काम करने का एक ही तरीका रहे। जो अध्यापक प्राइमरी स्कूलों में हैं, और तमिल या मराठी या बंगाली में पढ़ाते हैं, उनकी ख्वाहिश होती है कि उन की पदोन्नति हो और वे मिडिल स्कूल या हाई स्कूल में चले जायें। हम ने यह व्यवस्था की है कि अंग्रेजी और देशी भाषाओं के शिक्षकों में किसी प्रकार की असमानता न हो, और वह कभी भी नहीं होगी, मैं यह आश्वासन देना चाहता हूं।

श्री चतुर्भुज : रेलवे बोर्ड के अंदर कोई एजूकेशन का डायरेक्टर नहीं है तो क्या रेल मंत्री रेलवे बोर्ड के अंदर किसी शिक्षा के डायरेक्टर की नियुक्ति करने का आदेश देंगे ?

प्रो० मधु दंडवते : उन का जो सुझाव है उस पर हम विचार करेंगे लेकिन इन सब सवालों के बारे में विचार कर के हम लोगों ने आखिरी फैसले किए हैं। आप चाहते हैं कि बोर्ड की संख्या बढ़ा दें या कम कर दें तो उस के बारे में एक फैसला होना चाहिए। ऐडमिनिस्ट्रेटिव रिफार्म्स कमीशन ने बहुत सोच समझ कर हमारे सामने कुछ नक्शा रखा था। उस को हम अमल में लाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उनको भी कुछ सुझाव होगा तो हम जरूर कोशिश करेंगे।

श्री राम विलास पासवान : क्या रेल मंत्री को यह मालूम है कि विगत सरकार ने जो लोग अयोग्य भी थे, जिन को हिन्दी की कोई जानकारी थी ही नहीं, अंडर ग्रेज्युएट ग्रेज्यूएट और वह भी थर्ड डिवीजन थे उन लोगों को बड़े बड़े पदों पर बैठा दिया था हिन्दी विभाग में ? क्या सरकार कोई क्राइटीरिया निर्धारित कर के जो पुराने लोग पक्षपात पूर्ण तरीके से पिछली सरकार के द्वारा रखे गये थे उन को हटाएगी और फिर नये लोगों को उन की योग्यता के आधार पर रखेगी ?

MR. SPEAKER: Mr. Paswan, it does not arise out of the question at all.

Policy regarding laying of New Railway Lines

*689. SHRI BALWANT SINGH RAMOOWALIA: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that a change in the policy of laying new